भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-199

उत्तर देने की तारीख- 01.12.2025

मुंबई में उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी

†199. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री संजय दिना पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बढ़ती छात्र आबादी और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के बावजूद मुंबई में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस मांग को पूरा करने के लिए मुम्बई में एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नये उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ भूमि चिहिनित की है अथवा चर्चा शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महानगर क्षेत्र में पहुंच, सामर्थ्य और अनुसंधान क्षमता बढ़ाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध मौजूदा कॉलेजों को स्वायत्त अथवा मानित विश्वविद्यालयों में उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): वर्ष 2021-22 के एआईएसएचई रिपोर्ट अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 7003 उच्चत्तर शिक्षा संस्थान (एचईआई) हैं। मुंबई ज़िले में कई राष्ट्रीय महत्व वाले प्रमुख संस्थान, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे; भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), मुंबई और केंद्र से वित्तपोषित घोषित विश्वविद्यालय जैसे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान

(टीआईएसएस) आदि स्थित हैं, जो मुंबई के विद्यार्थियों की शैक्षिक तथा महत्वाकांक्षी जरूरतों को पूरा करते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। राज्य के विश्वविद्यालय संबंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं और राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। तथापि, केंद्र की सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है।

शिक्षा मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)" का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्धारित मापदंडों और नियमों के अनुरूप अपनी गुणवत्ता में सुधार हेतु वित्तीय सहायता देना है। सरकार ने जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण को "प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)" के रूप में आरंभ किया है, जिसके लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से वंचित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना है।

महाराष्ट्र राज्य में आरयूएसए और पीएम-उषा के तहत कुल 144 इकाइयों को 1,431.31 करोड़ रूपए की सहायता स्वीकृति दी गई है, जिसमें 24 विश्वविद्यालयों और 111 महाविद्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, आरयूएसए के पूर्ववर्ती चरणों में महाराष्ट्र के वाशिम, नंदुरबार और हिंगोली जिलों में 3 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों को 28 करोड़ रूपए की सहायता की स्वीकृति दी गई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों को क्षेत्र के अन्य संस्थानों को शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए अग्रणी संस्थानों के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17) के तहत उच्च शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। विस्तार मुख्यतः नए संस्थान स्थापित करने के बजाय मौजूदा संस्थानों की क्षमता को बढ़ाकर किया जाना था। महाराष्ट्र में पहले से ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा है।

इसके अतिरिक्त, "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" (डीटीबीयू) का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विश्वविद्यालय संस्थानों के विनियम*, 2023* के अनुसार विनियमित किया जाता है। महाराष्ट्र में वर्तमान में मुंबई में 8 स्थानों सहित कुल 23 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (आईडीटीबीयू) संचालित हो रहे हैं।.

*****